LOK SABHA

Friday, June 23, 1967/Asadha 2, 1889 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mr. Speaker: Shri Yashpal Singh.

Shri Umanath: Question 700 may also be taken up together. It is about supply of cotton to mills.

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): That is a different issue.

Forward Trading in Cotton

*691. **Shri Yashpal Singh:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether forward trading in cotton, groundnut, vegetable oils and jute is proposed to be banned; and

(b) if so, when?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) and (b). A statement is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-770/67].

श्री यशपाल सिंह : सरकार ने यह नहीं बतलाया कि इस में स्पेसिफिक डिलिवरी कंट्रेक्ट शामिल हैं या नहीं। अगर यह इस में शामिल हैं तो ठीक है नहीं तो फार्वर्ड ट्रेडिंग रहेगा, अगर आप उसको बैन न करेंगे।

श्री दिनेश सिंह : जैसा माननीय सदस्य जानते हैं आज कल स्पेसिफिक डिलिवरी कंट्रेक्ट दो प्रकार के हैं। एक तो वह हैं जो कि ट्रांस्फरेबल हैं जिन को हेज कहते हैं और जो सट्टे में आ जाते हैं, दूसरे नान-ट्रांस्फरेबल हैं जो कि फिक्स डिलिवरी कंट्रेक्ट हैं यानी एक मुकर्रर तारीख तक उन्हें जो सामान चाहिये वह मिल सके। अधिकतर चीजों को जिन का स्टेटमेंट में मैं ने जिक्र किया है सट्टा बन्द है। लेकिन स्पेसिफिक डिलिवरी कंट्रेक्ट जो नान-ट्रांस्फरेबल हैं उन की इजाजत है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि जो फार्वर्ड मार्केटिंग कमिशन बनाया गया है उस के मेम्बर्स कौन कौन से हैं और उस में किन किन क्लास का रिप्रेजेन्टेशन हुआ है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य शायद रिव्यू कमेटी की बात कर रहे हैं, जो बनी थी। उस कमेटी के आठ सदस्य हैं जिन के नाम यह हैं :

1. प्रो० एम० एल० दांतवाला
2. श्री ए० एस० नायक
3. श्री आर० टी० मीरचन्दानी
4. श्री जी० एम० लाड
5. श्री सी० एल० भीवाला
6. प्रो० एस० बी० कोगेकर
7. श्री आ० माधवन
8. श्री डी० आर० पेन्डसे

Shri M. Ansarey: Does the Government realise the importance of forward trading especially in cotton, and may I know the reasons why forward trading in cotton has not been allowed in the last two years?

Shri Dinesh Singh: Forward trading in the sense of transferable, which is

hedge, has not been allowed because the prices have ruled above the ceiling and as such, there has been shortage of cotton also, and it was felt that it was not necessary. Apart from that element, I think that at this stage when we have cotton shortage it would not be desirable to introduce a speculative tendency such as hedge in this

Shri Indrajit Gupta: The hon. Minister must be aware of the fact that one of the most highly speculative markets is that dealing with raw jute. May I know from him whether, in view of the fact that there is a continued shortage of raw jute in this country, any more stringent measures are proposed to be undertaken than those which have been adopted so far to regulate forward trading, and which have really failed to check speculation, as a result of which the industry on the one hand goes on complaining of high prices of raw jute, and on the other hand, the cultivators, the peasants who grow the raw jute, do not also get a fair price for it?

Shri Dinesh Singh: We anticipate this year a much better crop than before but we shall certainly look into any further stringent measures that may be necessary.

Shri R. Barua: The statement says that in Assam, Bihar, Orissa, Bengal etc. the futures or hedge contracts are not being permitted at present though there is no formal ban. What is the position. There is no ban and at the same time you do not permit it?

Shri Dinesh Singh: For a number of items there is no formal ban but by executive orders we have banned it for the time being.

Shri Yajnik: I want to raise the question about forward trading in groundnut and groundnut oil. Under the Essential Commodities Act, there shall be no forward trading in any items of edible oil and yet there is another law by which forward trading in groundnuts and groundnut oil had been permitted. I want to ask the Minister if, in view of the fact that there is serious scarcity of groundnut and groundnut oil in the whole country and also in view of the fact that very high prices are ruling in the market all over the country, the Government would not issue any order or take necessary action to see that all forward trading in groundnut oil and groundnut is immediately suspended or stopped?

Shri Dinesh Singh: Hedging in groundnuts is not permitted. Non-transferable specific delivery is permitted.

Shri Yajnik: That is no answer to the question. In view of the high ruling prices, would the Government consider the matter afresh and see that very severe restrictions on forward trading on these edible articles are stopped. There should be an answer to this question.

Shri Dinesh Singh: I thought I had mentioned earlier that there is no hedging in ground nut. That means there is no speculative forward trading. Only fixed delivery, specific date delivery trading which is non-transferable and which is not speculative is there.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस तरह के कंट्रैक्ट के लिये इजाजत इस लिये नहीं दी जा रही है क्योंकि जो अधिकतम दाम निश्चित किया गया था रूई का, उस से भी ज्यादा ऊंचे दाम चढ़ गये हैं। पिछली बार जब मैं ने यह सवाल उठाया था तब मुझ को बतलाया गया था कि व्यापार मंत्री के पास यह विषय है। आज व्यापार मंत्री मौजूद हैं, क्या मैं उन से पूछ सकता हूं कि रूई के अभाव को दूर करने के लिये क्या वह अभी से इस बात की घोषणा करेंगे कि रूई पर जो अधिकतम दाम लगाये गये हैं, सीलिंग प्राइस, उन को वह उठा लेंगे जिस से किसानों को प्रोत्साहन मिले और रूई की पैदावार बढ़ सके?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं कि रुई के ऊपर जो अधिकतम दाम रक्खे हुए हैं उन को हटा लेने से हमारे देश में जो कपड़े के दाम हैं उन के बढ़ जाने का अन्देशा है।

श्री मधु लिमये : नियन्त्रित कपड़ा सिर्फ अंशमात्र है।

श्री दिनेश सिंह : मैंने जो मिल मालिक हैं, जो रुई के व्यापारी और जो उस के पैदा करने वाले हैं उन से अभी बातें की हैं। मैं ने उन से कहा कि अगर हम मिल कर कोई ऐसा तरीका निकाल सकें जिस से कपड़े के दाम, जिन को हम ने कंट्रोल कर रक्खा है, न बढ़ें, तो हम इस पर विचार करने के लिये तैयार हैं।

श्री मधु लिमये : जो कपड़ा नियन्त्रित है उस के बारे में दो अलग अलग जवाब आ गये हैं। इस का भी खुलासा हो जाये। रुई तो 100 प्रतिशत नियन्त्रित है।

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं।

श्री मधु लिमये : कौन सी ऐसी रुई है जो कि नियन्त्रित नहीं है और कपड़ा कितना प्रतिशत नियन्त्रित है, वह बतलाइये।

श्री दिनेश सिंह : जो कपड़ा मिल्स में बनता है उस का लगभग 40 प्रतिशत नियन्त्रित है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सरकार को मालूम है कि पिछले सीजन में जब रुई का दाम मार्किट में खुला तो वह 175 रुपये क्विंटल खुला लेकिन जब माल मार्किट में आने लगा तब दाम गिर कर 140—145 रुपये क्विंटल हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा तरीका निकालेगी या सरकार होड़ करके रुई खरीदेगी ताकि जो भाव बांधा गया है उस भाव से रुई नीचे न आये साथ ही अगर दाम नीचे जाता है तो उसको उस बंधे भाव पर लाने के लिए सरकार स्वयं रुई खरीदे ?

श्री दिनेश सिंह : रुई की फ्लोर प्राइसेज निर्धारित हैं। उससे नीचे दाम से वह नहीं बिकेगी।

Shri D. N. Patodia: Futures trading is linked up with speculative transactions. It is an essential element of free market operations which in my opinion, only help in promoting and creating a long-range production programme for the industries, and therefore, may I know whether the Government feels that futures trading has only helped in balancing the fluctuation of prices and not in accelerating the fluctuation and to that extent if there is any case at all, it is the case of relaxing the futures control and not for further accelerating it?

Shri Dinesh Singh: It is difficult for me to enter into a discussion of the merits of this case.

Mr. Speaker: The Question Hour is turned into a discussion.

Shri D. N. Patodia: The question is whether there is any case for withdrawal or relaxing it.

Mr. Speaker: No. It should not turn into a discussion.

Shri R. K. Amin: Will the Minister explain whether in putting the restriction on forward trading, he makes any distinction between legitimate and illegitimate speculation and supposing there is a legitimate speculation, does he allow forward trading?

Shri Dinesh Singh: We are making a difference between legitimate purchases phased over a period and speculation as such. We are not permitting speculation.

श्री जार्ज फरनांडीज : मन्त्री महोदय ने उत्तर में कहा है मेरा जूट के बारे में पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा और त्रिपुरा को छोड़ कर देश के दूसरे भागों में हेज कांट्रैक्ट्स बैंड हैं। उन्होंने कहा है :

"Futures or hedge contracts are banned except in certain States.

In those areas also, futures or hedge contracts are not being permitted at present, though there is no formal ban. There is no proposal to impose a ban formally."

मेरा प्रश्न यह है कि क्या पिछले हफ्ते में पश्चिमी बंगाल के जूट व्यापारियों ने फार्वर्ड मार्किट कमीशन के सामने ऐसा कोई सुझाव भेजा है कि उनको फ्यूचर्ज और हेज कांट्रेक्ट्स अमल में लाने की इजाजत दी जाए और अगर भेजा है तो सरकार ने उस पर या फार्वर्ड मार्किट कमीशन ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी यह नहीं देखा है। पिछले सप्ताह भेजा है तो शायद अभी यहां न पहुंचा हो । जब आएगा तब मैं उसको देखूंगा ।

श्री अब्दुल गनी : जो वादा बाजारी करते हैं या जो सट्टा करते हैं क्या उनको लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि कितना सट्टा हुआ है ? क्या उनको सरकार को कोई इत्तिला देनी पड़ती है, अगर देनी पड़ती है तो क्या देनी पड़ती है ? अगर उनको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है तो क्या सरकार सोचेंगी कि उनको कोई न कोई लाइसेंस लेना पड़े सरकार से बाकायदा ताकि सरकार को पता चले कि इस वक्त रुई का या बाकी खाने पीने की चीजों का क्या हाल है ।

[जो वायदा बाजारी करते हैं या सट्टे करते हैं क्या उन को लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि कितना सट्टा हुआ है - क्या उन को सरकार को कोई इत्तिला देनी पड़ती है - अगर देनी पड़ती है तो क्या देनी पड़ती है - अगर उनको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है तो क्या सरकार सोचेंगी कि उनको कोई न कोई लाइसेंस लेना पड़े सरकार से बाकायदा ताकि सरकार को पता चले कि इस वक्त रुई का या बाकी खाने पीने की चीजों का क्या हाल है -]

श्री दिनेश सिंह : कुछ चीजों में तो कमिशन ने निर्धारित कर रखा है कि कौन कौन सी एसोसिएशंज हैं जिन के जरिये फार्वर्ड मार्किटिंग हो सकता है । सब का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या नहीं, मैं एक दम नहीं कह सकता।

Shri Ranga: Contrary to what was suggested by one of our friends here one of the Members put a supplementary—is it not a fact that the forward prices of groundnut and groundnut oil are lower than the ready market rates and they are not higher than the ceiling or the fair price fixed by the Government?

Shri Dinesh Singh: I could not say off-hand the prices that hon. Member may have in mind on a particular day but I will certainly find out.

Shri Ranga: Thank you.

Imported Raw Materials

+

*692. Shri B. S. Sharma:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Ram Singh Ayarwal:

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there are some industrial units which are totally dependent on the imported raw materials;

(b) if so, whether as a result of the restriction imposed by Government to import the required raw material, certain units had to close down;

(c) whether Government propose to take any steps to provide indigenous